

मैसर्स हिंदुस्तान ग्रेनाइट्स

बनाम

भारत संघ और अन्य

दिनांक: 3 अप्रैल, 2007

[न्यायाधीश: डॉ. अरिजितपसायत और एस. एच. कपाडिया,जेजे.]

सिविल मूल क्षेत्राधिकार : आई.ए. संख्या 1 और 2 में टी.सी. (सी) संख्या 165/2006 साथ में आई.ए. संख्या 2,4,5,6,7, और 10 टी.पी. (सी) संख्या 579/2006 टी.पी. (सी) संख्या 1067/2006 आई.ए. संख्या 1 और 2 टी.सी. (सी) संख्या 168/2006 एसएलपी (सी) संख्या 13670/2006 द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 13671/2006 सी.ए. संख्या 1802/2007

सी.ए. संख्या 1803/2007 सी.ए. संख्या 1804/2007 टी.सी. (सी) संख्या 166/2006 डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 600/2006 टी.सी. संख्या 167/2006 टी.सी. संख्या 1/2007 डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 22/2007 हिंदुस्तान ग्रेनाइट्स बनाम भारत संघ [न्यायमूर्ति कपाडिया]

एस एल पी (सी) संख्या 5376/2007

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति कपाडिया, 1. द्वारा दिया गया था। इस मामले में, हमें यह तय करना है कि क्या 30.8.05 की नीति परिपत्र और 31.8.05 की

अधिसूचना संख्या 24, जो विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के पैरा 6.8(ए) और पैरा 6.8(एच) में संशोधन करती है, वैध है या नहीं।

2. यह निर्णय 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) की बिक्री तक ही सीमित है।

3. भारत संघ द्वारा विभिन्न ईओयू के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

4. इस मामले में हमें जो बुनियादी मुद्दा तय करने की आवश्यकता है वह यह है: क्या 100% ईओयू द्वारा डीटीए बिक्री ईओयू योजना का एक अभिन्न अंग है?

5. सुविधा के लिए, हम नीचे दिए गए तथ्यों को पुनः प्रस्तुत करते हैं जैसा कि यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्टर्स [सिविल अपील संख्या 2007 एसएलपी (सी) संख्या (सीसी9879) के मामले में पुनः प्रस्तुत किया गया है। 2006)]।

6. निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) की अवधारणा को 1980 में एक्जिम नीति में पेश किया गया था। ई ओयू योजना भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। उक्त योजना के तहत, ई ओयू किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। 1992 में, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के माध्यम से एक्जिम नीति को वैधानिक मान्यता दी गई थी। 1991 में, ई ओयू को निर्यात आयुक्त से

अनुमति प्राप्त करने के बाद 5% तक अस्वीकृत और डी टी ए में माल बेचने की अनुमति दी गई थी। 1997 में, एक्विजिशन नीति 1997-2002 के तहत, ई ओयू को निर्यात के एफ ओबी मूल्य के 50% तक अस्वीकृत और माल बेचने की अनुमति दी गई थी, जो शुल्क के भुगतान और न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा आय (एनएफई) की पूर्ति के अधीन था। इस सीमा के ऊपर, ई ओयू तैयार उत्पादों को बेच सकता था जो पूर्ण शुल्क के भुगतान के खिलाफ स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकते थे।

7. 24.3.2000 को अभिषेक एक्सपोर्ट्स को विकास आयुक्त, नो एडा द्वारा संगमरमर की टाइलें और तैयार संगमरमर ब्लॉकों के निर्माण और निर्यात के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) प्रदान किया गया था। एल ओपी में यह निर्धारित किया गया था कि अभिषेक एक्सपोर्ट्स को एन एफ ई प्रतिशत बनाए रखना था और उन्हें न्यूनतम निर्यात दायित्वों को प्राप्त करना था। उक्त एल ओपी में यह भी निर्धारित किया गया था कि अभिषेक एक्सपोर्ट्स एक्विजिशन नीति 1997-2002 के प्रावधानों के अनुसार घरेलू बिक्री कर सकता है।

8. अभिषेक एक्सपोर्ट्स ने कच्चे आयातित संगमरमर और कच्चे शीसंगमरमर से बने तैयार संगमरमर का निर्यात शुरू किया। इस प्रकार आयात किया गया कच्चासंगमरमर शुल्क मुक्त था। एल ओपी के तहत,

अभिषेक एक्सपोर्ट्स को डी टी एमें बिक्री करने का अधिकार था, जो कि रियायती और पूर्ण शुल्क के भुगतान के अधीन था।

9. 1.4. 04 को एफ टी पी 2004-2009 लागू हुआ। हम यहां एफ टी पी 2004-2009 के पैरा 6.1,6.5, 6.8(ए), 6.8(बी),6.8(डी), 6.8(ई), 6.8(जी), 6.8(एच),उदघृत कर रहे हैं जो इस प्रकार है:-

अध्याय-6

पात्रता

6.1 इकाइयां जो अपनी संपूर्ण उत्पादन (डीटीए में अनुमेय बिक्री को छोड़कर) निर्यात करने का उपक्रम करती हैं, उन्हें निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) योजना, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) योजना या बायो-टेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी) योजनाके तहत माल के निर्माण के लिए, जिसमें मरम्मत, रीमेकिंग, रीकंडिशनिंग, री-इंजीनियरिंग और सेवाएं शामिल हैंस्थापित किया जा सकता है। हालांकि, ट्रेडिंग इकाइयां इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

शुद्ध विदेशी मुद्रा आय

6.5 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट को विदेशी मुद्रा का सकारात्मक शुद्ध लाभ प्राप्त करना होगा। शुद्ध विदेशी मुद्रा आय (एनएफई)

की गणना उत्पादन शुरू होने के पांच साल के ब्लॉक में संचयी रूप से की जाएगी।

तैयार उत्पादों / अस्वीकृत वेस्ट / स्क्रेप / अवशेष और उप-उत्पादों की डीटीए बिक्री

6.8 निम्नलिखित के अधीन ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों के पूरे उत्पादन का निर्यात किया जाएगा:

(क) जवाहरात और आभूषण इकाइयों को छोड़कर, इकाइयां रियायती शुल्क के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई की पूर्ति के अधीन निर्यात के एफओबी मूल्य के 50% तक माल बेच सकती हैं, डीटीए बिक्री के अधिकार के भीतर, यूनिट डीटीए में अपने उत्पादों को उन वस्तुओं के समान बेच सकती हैं जो इकाइयों से निर्यात की जाती हैं या निर्यात की जाने की उम्मीद है। मोटर कारों, मादक शराब, किताबों और चाय (तत्काल चाय को छोड़कर) के संबंध में रियायती शुल्क पर कोई डीटीए बिक्री अनुमेय नहीं होगी या एक पैकेजिंग / लेबलिंग / पृथक्करण / प्रशीतन इकाई / संघनन / सूक्ष्मीकरण / पल्वराइजेशन / दानेदारकरण / रासायनिक के मोनो-हाइड्रेट रूप को निर्जल रूप में या इसके विपरीत परिवर्तित करना और ऐसे अन्य आइटम जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है। एसईजेड में एक इकाई को की गई बिक्री को भी ईओयू द्वारा निर्यात के एफओबी मूल्य तक पहुंचने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा, बशर्ते ऐसी

बिक्री के लिए भुगतान ईईएफसी खाते से किया गया हो। डीटीए को बिक्री भी दवा उत्पादों (बल्कड्रग्स सहित) के पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता के अधीन होगी।

(ख) सेवाओं के लिए, जिसमें सॉफ्टवेयर इकाइयां शामिल हैं, डीटीए में बिक्री किसी भी मोड में, जिसमें ऑनलाइन डेटा संचार शामिल है, को भी निर्यात के एफओबी मूल्य के 50% तक और/या अर्जित विदेशी मुद्रा के 50% तक अनुमेय होगा, जहां ऐसी सेवाओं के भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं।

(घ) उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले स्क्रेप/कचरा/अवशेष या उसके संबंध में डीटीए में बेचा जा सकता है। जब तक कि एलओपी में विशेष रूप से निषिद्ध न हो, सीमा शुल्क अधिकारियों को पूर्व सूचना पर पैराग्राफ 6.8 (ए) के तहत बिक्री पर लागू होने वाले शुल्कों के भुगतान पर घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में रिजेक्ट्स बेचा जा सकता है। ऐसी बिक्री को डीटीए बिक्री पात्रता के विरुद्ध गिना जाएगा। निर्यात के एफओबी मूल्य के 5% तक के रिजेक्ट की बिक्री एनएफई की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी।

(च) उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले स्क्रेप/कचरा/अवशेष या उसके संबंध में डीटीए में बेचा जा सकता है, जैसा कि शुल्क छूट योजना के तहत अधिसूचित मानक इनपुट-आउटपुट मानदंडों के अनुसार रियायती शुल्क के भुगतान पर लागू होता है, जो निर्यात के एफओबी मूल्य के 50%

की समग्र सीमा के भीतर है। हालांकि, ऐसी बिक्री सकारात्मक एनएफई की उपलब्धि के अधीन नहीं होगी। उन मदों के संबंध में जो मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती हैं, विकास आयुक्त छह महीने की अवधि के लिए डेटा के आधार पर एड-हॉक मानदंड तय कर सकता है और इस अवधि के भीतर, वह बोर्ड ऑफ एडवाइजरी (बीओए) द्वारा मानदंड निर्धारित करवाएगा। डीटीए बिक्री के हकदार नहीं इकाइयों द्वारा अपशिष्ट/स्क्रेप/अवशेषों की बिक्री या डीटीए बिक्री पात्रता से परे बिक्री, पूर्ण शुल्क के भुगतान पर होगी। स्क्रेप/कचरा/अवशेष का निर्यात भी किया जा सकता है।

(ज) एलओपी में शामिल उप-उत्पादों को भी डीटीए में बेचा जा सकता है, बशर्ते कि पैराग्राफ 6.8 (ए) के समग्र अधिकार के भीतर लागू शुल्क के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति हो। डीटीए बिक्री के हकदार नहीं इकाइयों द्वारा उप-उत्पादों की बिक्री या पैराग्राफ 6.8(ए) की पात्रताओं से परे भी पूर्ण शुल्क के भुगतान पर अनुमेय होगी।

(झ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां पूर्ण शुल्क के भुगतान के विरुद्ध विकास आयुक्त को सूचना के तहत डीटीए में तैयार उत्पाद बेच सकती हैं, जो नीति के तहत स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं, बशर्ते उन्होंने सकारात्मक एनएफई प्राप्त कर लिया हो।

10. सारांशतः पैरा 6.8 (ए)के अनुसार, निर्यात के एफओबीमूल्य के 50% तक का माल सकारात्मक एनएफईकी पूर्ति के अधीन डीटीएम रियायती दर पर बेचा जा सकता है। इस सीमा में पैरा 6.8(घ) के तहत अस्वीकृत बिक्री, पैरा 6.8(च) के तहत अपशिष्ट की बिक्री और पैरा 6.8(ज) के तहत उप-उत्पाद शामिल हैं। पैरा 6.8(एच)के तहतपूर्णशुल्क के भुगतान के खिलाफ डीटीएम तैयार उत्पादों की बिक्री की जा सकती है, बशर्ते कि उक्त वस्तु नीति के तहत स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य हो। इसके अलावा, पैरा 6.8(एच)के तहत उप-उत्पादों की बिक्री और पैरा 6.8 के अधिकार से परे अपशिष्ट की बिक्री पूर्ण शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञेय थी। उपर्युक्तउदघृत पैराग्राफ ईओयू के संबंध में एफटीपी 2004-2009 के सार है।

11.16.12.04 को, विकास आयुक्त, नोएडा ने एल ओपी दिनांक 24.3.2000 के तहत अगले पांच वर्षों यानी 2005-2006 से 2009-2010 तक के लिए मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स द्वारा किए गए नवीनीकरण आवेदन को मंजूरी दी।

12. 16.12.04 को दी गई मंजूरी में कहा गया था कि मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के पास अगले पांच वर्षों में 9.90 करोड़ रुपये का एनएफईहोना चाहिए। एलओपीके तहत, निर्यातक को सकारात्मक एनएफई बनाए रखना आवश्यक था।

13. 31.8.05 को एफटीपी 2004-2009 के पैरा 6.8 (ए) और पैरा 6.8 (एच) में संशोधन करते हुए आक्षेपित परिपत्र जारी किया गया था। आक्षेपित परिपत्र द्वारा ईओयूजको आयातित कच्चे संगमरमर से तैयार संगमरमर की डी टी ए बिक्री को तत्काल प्रभाव से रोका गया था। यह वह अधिसूचना है जो चुनौती का विषय है।

14. मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, 300 लाख रुपये का निवेश किया गया था; इसने भारत सरकार की नीति के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर से 2.30 लाख रुपये का ऋण लिया था और उपरोक्त निवेश करके इसने अपनी स्थिति में काफी बदलाव किया था। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, आक्षेपितपरिपत्रके कारण, डीटीएमें इसके द्वारा बेचे जाने वाले संगमरमर की मात्रा कम हो गई। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, आक्षेपित परिपत्र द्वारा एफटीपी 2004-2009 में इस तरह का संशोधन सार्वजनिक हित के किसी भी तत्व से रहित था। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, आक्षेपित परिपत्र ई ओयू योजना की मूल विशेषता के खिलाफ था।

15. राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। 29.09.06 के आदेश के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स द्वारा दायर रिट याचिका को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

16. मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, 30.8.2005 के आक्षेपित परिपत्र द्वारा विशेष आयात लाइसेंस इकाइयों (एस आई एल यूनिट्स) द्वारा आयात की जाने वाली मात्राको मनमाने ढंग से 80,000 एम टी से बढ़ाकर 1.30 लाख एम टी कर दिया गया था। 30.8.05 के परिपत्र को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह 100% ई ओयू और एस आई एल इकाइयों के बीच अनुचित रूप से भेदभाव करता है; यह कि आक्षेपित परिपत्र चयनित आयातकों को लाभ देता है; यह कि आक्षेपित परिपत्रका प्रभाव घरेलू बाजारमें उपयोग के लिए आयातित कच्चे संगमरमर ब्लॉकों की उपलब्धता को बढ़ाना थाऔर बिना किसी कारण के आयात का अधिकार केवल आक्षेपित परिपत्र दिनांक 31.8.05 द्वारा अनुचित रूप से एस आई एल इकाइयों तक सीमित कर दिया गया है। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, आक्षेपित परिपत्र / अधिसूचना के कारण घरेलू क्षेत्र में ई ओयू द्वारा बेचे जाने वाले संगमरमर की मात्रा कम हो गई है और उसी आयातित कच्चे संगमरमर से एस आई एल इकाइयों द्वारा बेचे जाने वाले संगमरमर की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ई ओयू को नुकसान हुआ है। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, आक्षेपित परिपत्र / अधिसूचना सार्वजनिक हित के खिलाफ था क्योंकि एस आई एल इकाइयों काकोई निर्यात दायित्व नहीं था, वे विदेशी मुद्रा अर्जक नहीं थे; उन्हें कमदर का शुल्क देना पड़ता था और परिणाम स्वरूप मैसर्स अभिषेक

एक्सपोर्ट्स के अनुसार आक्षेपित परिपत्र / अधिसूचना सार्वजनिक हित में नहीं था। इस के अलावा, मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, डी टी ए बिक्री ई ओयू योजना की एक आवश्यक विशेषता थी क्योंकि पैरा 6.1 के अनुसार, 100% ई ओयू ने ई ओयू योजना के तहत डी टी ए में अनुज्ञेय बिक्री को छोड़कर, माल के अपने पूरे उत्पादन का निर्यात करने का उपक्रम किया था, और इसलिए, डी टी ए बिक्री ई ओयू योजना का एक अभिन्न अंग थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि डी टी ए बिक्री की अनुमति केवल तभी दी गई थी जब ईओयूने अपने निर्यात दायित्वों को पूरा किया और सकारात्मक एन एफ ई हासिल किया, और इसलिए, एन एफ ई प्राप्त करने पर ई ओयू को लाभ प्रदान कर नासकारात्मक उद्देश्य था और इसका आयातित कच्चे माल से कोई संबंध नहीं था जिसमें से निर्यात किए जाते हैं। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, डी टी ए बिक्री के अभाव में, एक ई ओयू अपने पूरे उत्पादन को निर्यात बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, डीटीएबिक्री पर कुल प्रतिबंध के कारण संगमरमर टाइल्स की उनकी सूची कारखाने में जमा होने की संभावना है, जिससे कार्यशील पूंजी और धन अवरुद्ध हो जाएगा, जो अन्यथा स्थानीय बाजार में निपटाए जाते थे। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, बिना संशोधित नीति ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात व्यवसाय में गिरावट के खिलाफ एक इन्सुलेशन / बचाव प्रदान किया था। मैसर्स

अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, एक ई ओयू मंदी के मौसम में घरेलू बाजार में संगमरमर टाइल्स बेच सकता है ताकि एक ईओयूका उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधि प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार आक्षेपित परिपत्र / अधिसूचनाके कारण मंदी के दौरान एक निष्क्रिय क्षमता अर्जित होगी। इसके अलावा, बिना संशोधित नीति के तहत, नुकसान के मामले में, एक ई ओयू डी टी ए बिक्री द्वारा नुकसान को अच्छा कर सकता है, और इसलिए, ऐसी बिक्री ई ओयू योजना की एक आवश्यक विशेषता थी। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, डी टी ए बिक्री संयंत्र को अधिकतम क्षमता पर चलाने, प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजार में उत्पादन की लागतको कम करने, निर्यात अधिशेष से निपटने और निर्यात आदेशों को रद्द करने परनिर्यात उत्पादों के निपटान के लिए आवश्यक थी। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, आक्षेपित परिपत्र/अधिसूचनाको 100% ई ओयू की कीमत पर एस आई एल इकाइयों की रक्षा के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, विवादित संशोधन ईओयू के व्यवसाय को बाधित करेगा और यह घरेलू बाजार में आयातित कच्चे संगमरमर से बने 1.30 लाख मीट्रिक टन तैयार संगमरमर उत्पाद से भर जाएगा जो सार्वजनिक हित में नहीं होगा। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, विवादित सर्कुलर / अधिसूचना गुजरात के संगमरमर उद्योग की रक्षा के लिए जारी किया गया

है जो संगमरमर की एसआईएल आधारित आयात नीति का प्राथमिक लाभार्थी है। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्टर्स ने आगे प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का वर्तमान मामले में उल्लंघन किया गया है क्योंकि विवादित सर्कुलर / अधिसूचना ईओयू की कीमत पर एस आई एल आयातकों को रियायत देने के लिए जारी किया गया है।

जब उपरोक्त मामला इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो 10.1.07 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

"ओजीएललाइसेंस के तहत 100% ई ओयू द्वारा डी टी ए बिक्री पर प्रतिबंध और एस आई एल योजना के तहत 1999-2001 के बीच कच्चे संगमरमर का आयात करने वाले आवेदकों को लाइसेंस जारी करने को सीमित करना, आक्षेपित नीति परिपत्र संख्या 24 दिनांक 30.8.2005, संख्या 34 दिनांक 30.11.2005 और अधिसूचना संख्या 23 और 24 दिनांक 31.8.2005 (इसके बाद आक्षेपित नई नीति के रूप में संदर्भित) को विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। 29.9.2006 के आदेश के अनुसार, उक्त रिट याचिकाओं को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों और इस तथ्य के मद्देनजर कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए घरेलू उपयोग कर्ताओं का अधिकार 31.3.2007 को समाप्त होने जा रहा है, निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया जाता है।

डी जी एफ टी उन आवेदकों को लाइसेंस देने का हकदार होगा जो नीति परिपत्र संख्या 24 दिनांक 30.8.2005 के तहत हकदार हैं। उस सीमा तक हमारा 29.9.2006 का आदेश रद्द कर दिया गया है।"

टी.पी. (सी) नंबर 579/06 में, जो विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा दायर किया गया था, यह अन्य बातों के साथ कहा गया है कि व्यापारियों से प्राप्त अभ्यावेदन और डीजीएफटीद्वारा एकत्रित सामग्री (शिकायतों सहित) के कारण, आक्षेपित नई नीति लागू हुई। व्यापार के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह हुआ। नई नीति की व्यापक विशेषताएं और नीति को लागू करने के कारण T.P.(सी) संख्या 579/06 के पैराग्राफ 15, 16 और 17 में दिए गए हैं। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यक सामग्री प्रभावित 100% ईओयूको नहीं दी गई थी। जिन्होंने हमारे सामने शिकायत की है कि प्रभावित इकाइयों को कोई अवसर दिए

बिना एफटीपीमें आक्षेपितनीति के माध्यम से परिवर्तन किए गए हैं। इस स्तर पर हम यह बता सकते हैं कि भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हमारे सामने कहा कि आक्षेपितनीतिगत निर्णय कुछ सामग्री (शिकायतों/प्राप्त अभ्यावेदन सहित) पर लिया गया है जिसे वह संबंधित ईओयूजको प्रकट करने के लिए तैयार है। तदनुसार, हम डीजीएफटीको निर्देश देते हैं कि वह अपने कब्जे में मौजूद सामग्री को प्रभावित ईओयूको प्रदान करे, जिन्होंने 15.1.2007 को या उससे पहले रिट याचिका दायर की है। उक्त याचिकाकर्ता (ईओयू) जिन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है, डीजीएफटीसे सामग्री (शिकायतों सहित) प्राप्त होने के बाद और उसके 10 दिनों के भीतर डीजीएफटीको अभ्यावेदन करेंगे। तत्पश्चात, डीजीएफटीकानून के अनुसार मामले का फैसला करेगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि डीजीएफटी के लिए यदि संभव हो तो मामले को साम्यरूप से सुलझाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। हालांकि, एक बिंदु का उल्लेख करने की आवश्यकता है। मैसर्स हिंदुस्तान ग्रेनाइट्स की ओर से कहा गया है कि उनके पास संचित अपशिष्ट हैं जिन्हें वे अप्रकाशित नीति के तहत डीटीए में

बेचने के हकदार हैं। मैसर्स हिंदुस्तान ग्रेनाइट्स की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने शुद्ध विदेशी मुद्रा आय के बेंचमार्क को पूरा किया है, और इसलिए, वे पूर्ण शुल्क के भुगतान पर घरेलू बाजार (डीटीए) में संचित अपशिष्ट को पैरा 6.8 (एच) के तहत बेचने के हकदार थे। इस बिंदु पर, मैसर्स हिंदुस्तान ग्रेनाइट्स भी संचित अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में तथ्य और आंकड़े देते हुए अभ्यावेदन कर सकती हैं और यदि संभव हो तो डीजीएफटी के लिए डीटीए में उक्त अपशिष्ट की बिक्री के संबंध में प्रश्न तय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

यह प्रश्न कि क्या आक्षेपित परि पत्र/अधिसूचना नीति में बदलाव का गठन करती है या क्या यह प्रश्न गत मौजूदा नीति के भीतर एक विस्तार का विषय है, जिस पर सुनवाई की अगली तारीख को फैसला किया जाएगा जब हम मामले के गुण-दोष की जांच करेंगे।

डीजीएफटी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, हम अगली सुनवाई में मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेंगे। इस बीच, डीटीए बिक्री करने वाली ईओयू इकाइयों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। नतीजतन, राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक

26.10.2005 के डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 5811/05

में पारित अंतरिम आदेश को स्थगित रखा जाएगा।

31.1.2007 तक स्थगित कर दिया गया।"

7.2.07 को, विदेश व्यापार महानिदेशकनेपक्षों को सुनने और उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद मैसर्स हिंदुस्तान ग्रेनाइट्स लिमिटेड, मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स, मैसर्स पैसिफिक इंडस्ट्रीजलिमिटेड, मैसर्स जैन ग्राणीमार्मो प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मार्बल आर्ट (सभी 100% ईओयू) द्वारा किए गए विभिन्न अभ्यावेदन को खारिजकरते हुए एक आदेश पारित किया। उक्त आदेश भी हमारे समक्ष चुनौती के अधीन है।

उक्त आदेश ने 100% ईओयूऔरएसआईएलइकाइयों के संबंध में 31.8.05 को लिए गएनिर्णय को बिना किसी बदलाव के फिर से पुष्टि की है। इस संबंध में, मैसर्सअभिषेक एक्सपोर्ट्स की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि महानिदेशक ने यहमानने में गलती की थी कि ईओयूस्वदेशी संगमरमर से तैयार उत्पाद बनाकर औरउक्त तैयार उत्पादों को निर्यात करके डीटीएसुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे, बजाय इसके कि आयातित संगमरमर से तैयार उत्पाद बनाकर निर्यात किया जाए। मैसर्सअभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, एफटीपी 2004-2009 विशेष रूप से ईओयूको आयातितसंगमरमर से बने तैयार उत्पादों कोएफओबीमूल्य का 50% तक,रियायती दर परडीटीएमें बेचने की अनुमति देता है, पैरा 6.8(ए)के

अनुसार। यह कि उक्तनीति ने ईओयूको डीटीएममें निर्यात के एफओबीमूल्य के 50% से अधिक कुछ भी पूर्णशुल्क [पैरा 6.8(एच)] के भुगतान पर बेचने की अनुमति दी, बशर्ते कि ईओयूएकसकारात्मक एनएफईबनाए रखें।मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, उपरोक्तप्रणाली सात वर्षों तक संचालित हुई। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, उपरोक्त प्रणाली को प्रक्रिया की हैंडबुक में अनुमति दी गई है, जिसके तहतहर आयात खेप को निर्यात के साथ स-संबंधित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के अनुसार, पिछले सात वर्षों से कार्यान्वयनप्राधिकरण ने स्वदेशी संगमरमर से तैयार माल के निर्माण पर आपत्ति नहीं कीहै और उक्त प्राधिकरण ने कभी भी इस तरह के तैयार माल को नीति के उल्लंघन यादुरूपयोग के रूप में निर्यात करने पर आपत्ति नहीं की है। मैसर्स अभिषेकएक्सपोर्ट्स के अनुसार, महानिदेशक ने यह मानने में गलती की थी कि आक्षेपितसंशोधन घरेलू संगमरमर उद्योग की रक्षा के लिए था। मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्सके अनुसार, नीति में बदलाव के कारण, जो ईओयूपहले घरेलू बाजार से कच्चासंगमरमर खरीदकर तैयार उत्पाद बना रहे थे और उन्हें निर्यात कर रहे थे, अबवे ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह कि, संशोधित नीति के तहत ईओयूको अब आयातितसंगमरमर से बने तैयार उत्पादों का निर्यात करना आवश्यक है। मैसर्स अभिषेकएक्सपोर्ट्स के अनुसार, एसआईएलइकाइयों के संबंध में नीति में बदलाव के कारणउन्हें 68,000

एमटीकी तुलना में 1.30 लाख एमटीके आदेश के लिए संगमरमर के आयातकी अनुमति देना घरेलू खनन उद्योग को प्रभावित करेगा।मैसर्स अभिषेकएक्सपोर्ट्स के अनुसार, महानिदेशक ने यह मानने में गलती की थी कि डीटीएमेंआयातित कच्चे संगमरमर काविचलन हुआ, जिसने संगमरमर को प्रतिबंधित श्रेणीमें रखने के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया। इस संबंध में, मैसर्स अभिषेकएक्सपोर्ट्स का तर्क है कि कोई विचलननहीं था क्योंकिदिनांक 31.08.2005 को संशोधन से पहले डीटीए बिक्री को विशेष रूप से एफटीपी 2004-2009 के पैरा 6.8(ए)और 6.8(एच)के तहत अनुमति दी गई थी और इसलिए जैसा कि पाया गया कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था।

हम निम्नलिखित कारणों से आक्षेपितपरिपत्र/अधिसूचना को चुनौती देने में कोई गुणावगुण नहीं पाते हैं। सबसेपहले, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि असंशोधित एफटीपी 2004-2009 के पैरा 6.1के तहत, 100% ईओयूजनेडीटीएमें अनुमेय बिक्री को छोड़कर अपने पूरेउत्पादन का निर्यात किया। इसलिए, डीटीएबिक्री एक अपवाद या एकआकस्मिक सुविधा का गठन करती है। डीटीएबिक्री ईओयूयोजना का एक अभिन्न अंगनहीं थी। पैरा 6.1 के तहत, ईओयूको इस शर्त पर स्थापित करने की अनुमति दी गईथी कि वे अपने पूरे उत्पादन का निर्यात करेंगे। यह इस शर्त पर है कि 100% ईओयूसीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत विभिन्न

लाभोंका लाभ उठा सकते हैं। उक्त डीटीएबिक्री या अस्वीकार की बिक्री अपवाद थे। डीटीएबिक्री ईओयूयोजना का एक अभिन्न अंग नहीं थी इस अर्थ में कि यदि उचितकारणों से यदि इन अपवादों को समाप्त कर दिया जाता है, जैसा कि इस मामले में है, तो योजना अकार्यशील हो जाएगी। वास्तव में, मैसर्स हिंदुस्तान ग्रेनाइट्स आज भी आक्षेपित संशोधन के बाद घरेलू कच्चे माल के उपयोग के बिना काम करता है। इसलिए, डीटीए बिक्री ईओयू योजना का एक अभिन्न अंग नहीं है। दूसरे, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 100% ईओयूज संगमरमर के ब्लॉक का आयात कर रहे हैं, जिससे वे संगमरमर की टाइलें / स्लैब का उत्पादन कर रहे हैं और जो वे निर्यात कर रहे हैं वह उक्त संगमरमर की टाइलें / स्लैब हैं। हालांकि, महानिदेशक ने पिछले सात वर्षों के दौरान पाया कि संगमरमर टाइलों / स्लैब का पूरा निर्यात खराब गुणवत्ता वाले स्वदेशी कच्चे संगमरमर ब्लॉक से किया जाता है। दूसरी ओर, यह पाया गया कि डीटीए में संगमरमर टाइलों/स्लैब की पूरी बिक्री समृद्ध अच्छी गुणवत्ता वाले आयातित कच्चे संगमरमर ब्लॉक से होती है। इसलिए, 100% ईओयू द्वारा डीटीए बिक्री अब आक्षेपित परिपत्र / अधिसूचना के तहत अस्वीकृत है। तीसरा, उपरोक्त अभ्यासके कारण, महानिदेशक ने पाया है कि चार से पांच 100% ईओयूज कच्चे संगमरमर को स्पष्ट रूप से निर्यात के लिए आयात कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव में थोड़ी पॉलिशिंग के बाद डीटीए में बेचा जाता है। संगमरमर एक प्रतिबंधित वस्तु

है। उपरोक्त अभ्यास के कारण, महानिदेशक ने संगमरमर के प्रतिबंधित आयात नीति को 100% ईओयू योजना के दौरान (असंशोधित) उल्लंघन पाया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, शुद्धविदेशी मुद्रा अर्जन की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्य अंतर के कारण, आक्षेपित अभ्यास, के तहत घरेलू आदानों द्वारा आयातित आदानों का प्रतिस्थापन है। 100% ईओयू द्वारा कच्चे संगमरमर ब्लॉकों के आयात की अनुमति देने के पीछे तर्क यह था कि कच्चे माल का उपयोग निर्यात उत्पादन के लिए किया जाएगा और यह डीटीए में नहीं जाएगा, संगमरमर को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने के उद्देश्य को पराजित करेगा। ईओयू योजना के पीछे उद्देश्य तैयार उत्पादों के निर्माण के लिए आयातित कच्चे माल की खपत है जिन्हें निर्यात किया जाना है। यदि वह सुविधा घरेलू रूप से खरीदे गए आदानों द्वारा आयातित आदानों के प्रतिस्थापन की ओर ले जाती है तो सुविधा को बंद करना होगा। यह बंद आक्षेपित परिपत्र अधिसूचना द्वारा किया गया है। चौथा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, संगमरमर प्रतिबंधित श्रेणी के तहत एक आइटम है। इसे प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसे केवल राजस्व-सृजन संसाधन के रूप में नहीं माना जाता है। इसे प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है क्योंकि खनन उद्योग उस संसाधन पर निर्भर करता है। यह रोजगार पैदा करता है। खनन रोजगार पैदा करता है। संगमरमर खनन उद्योग में आवश्यक एक इनपुट है। आक्षेपित प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप, भारतीय बाजार

आयातित वस्तुओं से भर जाता है जिसके परिणामस्वरूप खनन उद्योग में बेरोजगारी होती है। पांचवां, आक्षेपित परिपत्र / अधिसूचना द्वारा सरकार ने एनएफई आय प्राप्त करने के लिए घरेलू कच्चे संगमरमर ब्लॉकों की खरीद को रोक दिया है। यह आक्षेपित परिपत्र / अधिसूचना के पीछे प्रमुख उद्देश्य है। यह सच है कि असंशोधित नीति का आयात किए गए इनपुट और निर्यात किए गए तैयार उत्पाद के बीच कोई संबंध नहीं था। वह खामी थी। एनएफई प्राप्त करने के लिए घरेलू कच्चे संगमरमर ब्लॉकों की खरीद को रोकने के लिए, डीटीए बिक्री को प्रतिबंधित करना पड़ा। संशोधित नीति के अनुसार 100% ईओयू को अब आयातित कच्चे संगमरमर ब्लॉकों से संगमरमर टाइल्स/स्लैब (तैयार उत्पाद) का उत्पादन करने की आवश्यकता है और इस प्रकार संशोधित नीति इन 100% ईओयू द्वारा एनएफई प्राप्त करने के लिए घरेलू कच्चे संगमरमर ब्लॉकों की खरीद को रोकती है। अंत में, 4 से 5 100 प्रतिशत ईओयू के मुकाबले 20 से 25 एसआईएल इकाइयां (पात्र पाए गए) हैं और इसलिए, मात्रा 68000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1.30 लाख मीट्रिक टन कर दी गई है।

21. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम 100% ईओयू की ओर से उद्धृत न्यायिक द्रष्टांत का उल्लेख करना चाहेंगे।

22. बन्नारी अम्मन सुगर्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य, [2005] 1 एससीसी 625 के मामले में, इस

न्यायालय की खंडपीठ ने हम में से एक, पासायत, जेके माध्यम से अभिनिर्धारित करते हुए, यह माना है कि गन्ने पर खरीद कर से छूट सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिलों के पक्ष में दी गई जिनका उत्पादन 300 लाख रुपये से अधिक था, वे कर लाभ के हकदार थे और सरकार उस लाभ को वापस लेने के लिए सही नहीं थी, खासकर जब उद्योग सरकार द्वारा किए गए अभिकथन के आधार पर स्थापित हुआ था। वचनविबंधके सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, यह पैरा '16' और '17' के माध्यम से देखा गया है कि यदि राज्य एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से और सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से तय किए जाने वाले उचितता की सीमा के भीतर कार्य करता है तो प्रतिबंध को केवल इसलिए अनुचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह कठोरता से संचालित होता है। हमारे विचार में, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, हम संतुष्ट हैं कि आक्षेपित संशोधन सार्वजनिक हित की कसौटी पर खरा उतरता है और यह 100% ईओयू पर लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में उचितता की कसौटी को भी पूरा करता है।

23. इसी तरह, यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी और अन्य, [2003] 5 एससीसी437 के मामले में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने हम में से एक, पासायत, जे के माध्यम से अभिनिर्धारित करते हुए, यह माना है कि यदि राज्य राष्ट्रीय प्राथमिकता और अच्छी व्यापार नीतियोंको ध्यान में रखते हुए उचित कार्य करता है तो

यह नहीं कहा जा सकता है कि आर्थिक हित में लगाए गए प्रतिबंध अनुचित हैं, भले ही वे कठोरता से लागू हों [देखें: पैरा '22' और '23']।

24. यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम मेसर्स एशियनफूड इंडस्ट्रीज, (2006) 12 स्केल 105 के मामले में, जिस पर मेसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के वकील द्वारा भरोसा किया गया है, इस न्यायालय की खंडपीठ ने माना है कि विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तिका के साथ एक समग्र योजना का गठन करती है। हम इस प्रस्तावके साथ विवाद नहीं करते हैं। प्रक्रिया पुस्तिका केवल नीति को लागू करती है। यह केंद्र सरकार को नीति बदलने से नहीं रोकता है। उक्त निर्णय के पैरा '29' और '30' के माध्यम से यह विशेष रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार 1992 के अधिनियम की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात पर रोक लगा सकती है। उस मामले में, यह न्यायालय निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के सवाल से संबंधित था। इस मामले में ऐसा नहीं है। हमारे सामने मामले में एक आकस्मिक घटना थी। 100% ईओयूकोउन नुकसानों से बचाने के लिए सुविधा दी गई है जो विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के कारण उत्पन्न हो सकते हैं जो सुविधा हटा दी जाती है। हमारे विचार में, सार्वजनिक हित में, केंद्र सरकार को मौजूदा नीति के साथ छेड़छाड़ करके खामी को दूर करने से कोई भी नहीं रोकता है जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है।

उपरोक्तकारणों से 100% ईओयू द्वारा डीटीए बिक्री को अस्वीकार करने की तुलना दालोंके निर्यात पर कुल प्रतिबंध के साथ नहीं की जा सकती है जो कि मैसर्स एशियनफूड इंडस्ट्रीज (सुप्रा) के मामलेमें थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, डीटीए बिक्री ईओयू योजना का एक अभिन्न अंग नहीं थी, इसलिए उपरोक्त निर्णय लागू नहीं होता है।

25. उपरोक्त कारणों से, हम उपरोक्त 100% ईओयू द्वारा आक्षेपित परिपत्र दिनांक 30.8.05 और अधिसूचना दिनांक 31.8.05 को चुनौती देने में कोई गुणावगुणनहीं पाते हैं। तदनुसार, हम परिपत्र दिनांक 30.8.05 और अधिसूचना दिनांक 31.8.05 की वैधता को बनाए रखते हैं। अंतरिम आवेदन, दीवानी अपील, स्थानांतरण याचिका, रिट याचिका और स्थानांतरण मामलों का निपटारा तदनुसार किया जाता है, जिसमें खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

26. जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह निर्णय 100% ईओयू द्वारा आक्षेपितपरिपत्र/अधिसूचना को चुनौती देने तक ही सीमित है और इसका एसआईएल इकाइयों द्वारा चुनौती से कोई लेना-देना नहीं है, जिन्होंने अलग-अलग याचिकाएँ दायर की हैं, जिन्हें सामान्य तौर पर सुना जाएगा। डी.जी.आई.ए एस., अपीलें, स्थानांतरण याचिका रिट याचिका और स्थानांतरण मामलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीष कुमार वैष्णव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।
